ग्रामीण स्थानीय निकायों के अनुदान: 16वें वित्त आयोग की बढ़त

शासन / पंचायती राज / राजकोषीय संघवाद | समाचार संदर्भ: पंचायती राज मंत्रालय के 12 वर्षों का ब्योरा, PIB 15 जून 2026 | प्रकाशित: 18 अक्टूबर 2026

पृष्ठभूमि और संदर्भ

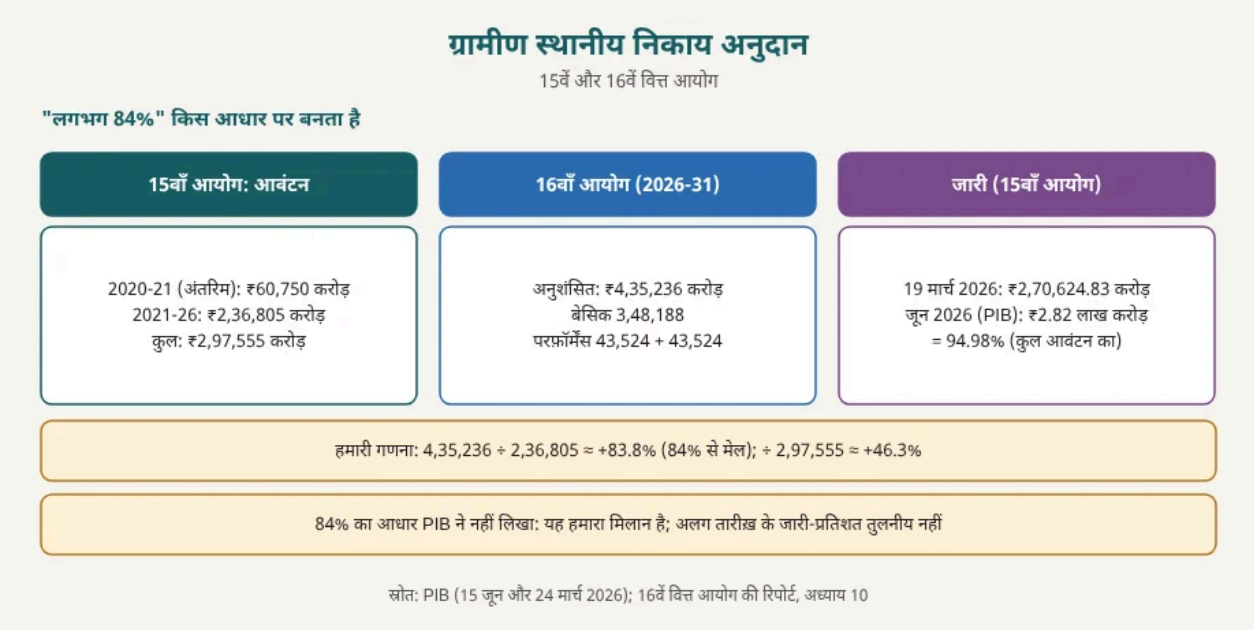
पंचायती राज मंत्रालय की 15 जून 2026 की PIB विज्ञप्ति “12 वर्षों के पंचायत सुधार और नवाचार” का सरकारी सार है, इसलिए इसके आँकड़े मंत्रालय के अपने दावे हैं। इसमें प्रशिक्षण, SVAMITVA, e-GramSwaraj और वित्त आयोग के अनुदान एक साथ आए हैं। यह लेख केवल ग्रामीण स्थानीय निकायों (RLB) के अनुदान वाले हिस्से को जाँचता है। जाँच के लिए इसी मंत्रालय के लोकसभा उत्तर (PIB, 24 मार्च 2026), 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के स्थानीय निकाय अध्याय और केंद्र सरकार के कार्रवाई-ज्ञापन के संबंधित अंश भी पढ़े गए।

खबरों में क्यों

PIB की 15 जून 2026 की विज्ञप्ति के अनुसार 15वें वित्त आयोग की अवधि (2020–26) में ग्रामीण स्थानीय निकायों को ₹2.82 लाख करोड़ जारी हुए, जो कुल आवंटन का 94.98 प्रतिशत है। विज्ञप्ति में यह भी कहा गया कि 2026-27 से 2030-31 के लिए 16वें आयोग ने ₹4,35,236 करोड़ की अनुशंसा की है, जो 15वें आयोग के आवंटनों से “लगभग 84%” अधिक है। विज्ञप्ति तुलना का आधार नहीं बताती।

मुख्य अवधारणा: जारी, आवंटित और अनुशंसित राशि अलग हैं, और हर प्रतिशत का आधार चाहिए

94.98% जारी राशि का आवंटन से अनुपात है। “लगभग 84%” अनुशंसित राशि की पिछले चक्र के आवंटन से तुलना है। दोनों प्रतिशत अलग आधार पर हैं। नीचे दिए आधिकारिक आँकड़ों से हमारी गणना में 84% का आधार 15वें आयोग का 2021-26 का पाँच वर्षीय आवंटन बैठता है, कुल 2020-26 आवंटन नहीं।



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

मुख्य तथ्य और आंकड़े

15वाँ वित्त आयोग: आवंटन	**PIB (24 मार्च 2026, लोकसभा उत्तर): ₹60,750 करोड़ अंतरिम वर्ष 2020-21 के लिए और ₹2,36,805 करोड़ अंतिम अवधि 2021-26 के लिए, यानी कुल ₹2,97,555 करोड़। 16वें आयोग की रिपोर्ट भी 2021-26 के लिए RLB का ₹2,36,805 करोड़ देती है।**
15वाँ वित्त आयोग: जारी राशि	PIB (24 मार्च 2026): 19 मार्च 2026 तक ₹2,70,624.83 करोड़ जारी। PIB (15 जून 2026): ₹2.82 लाख करोड़, कुल आवंटन का 94.98%। दोनों की तारीख़ अलग है।
16वाँ वित्त आयोग (2026-27 से 2030-31)	PIB (24 मार्च 2026): RLB के लिए कुल ₹4,35,236 करोड़ की अनुशंसा: बेसिक ₹3,48,188 करोड़, RLB परफ़ॉर्मेंस ₹43,524 करोड़, राज्य परफ़ॉर्मेंस ₹43,524 करोड़। बेसिक का आधा (₹1,74,094 करोड़) टाइड और आधा अनटाइड है। कार्रवाई-ज्ञापन के अनुसार बेसिक और परफ़ॉर्मेंस 80:20 में हैं।
विज्ञप्ति के अन्य दावे (मंत्रालय के)	RGSA में 4.10 करोड़ प्रतिनिधि और कर्मी (संचयी) प्रशिक्षित; SVAMITVA में 10 जून 2026 तक लगभग 3.18 करोड़ संपत्ति कार्ड; e-GramSwaraj और PFMS के मंच पर 10 जून 2026 तक ₹3.16 लाख करोड़ से अधिक के ऑनलाइन लेन-देन।

आँकड़ों की जाँच: “लगभग 84%” का आधार और जो मेल नहीं खाता

जो मेल खाता है (हमारी गणना): 4,35,236 ÷ 2,36,805 = 1.838, यानी लगभग 83.8%, जो “लगभग 84%” से मेल खाता है। यानी 16वें आयोग के पाँच वर्ष की तुलना 15वें आयोग के 2021-26 के पाँच वर्ष से है। विज्ञप्ति स्वयं यह आधार नहीं लिखती, इसलिए यह हमारा मिलान है, PIB का कथन नहीं। 15वें आयोग के कुल ₹2,97,555 करोड़ (अंतरिम 2020-21 सहित) से तुलना करने पर बढ़त लगभग 46.3% बैठती है।

जो मेल खाता है: जारी का प्रतिशत: 94.98% × ₹2,97,555 करोड़ लगभग ₹2.826 लाख करोड़ आता है, जो विज्ञप्ति के “₹2.82 लाख करोड़” से मेल खाता है (हमारी गणना)। यानी 94.98% का आधार अंतरिम 2020-21 सहित पूरा आवंटन है,

जबकि 84% का आधार, हमारे मिलान में, उसके बिना। मार्च 2026 के ₹2,70,624.83 करोड़ से यह राशि अधिक है, पर दोनों की तारीख़ अलग हैं, इसलिए हम इसे विसंगति नहीं कहते।

जो तुलनीय नहीं है और अनसुलझा है: 16वें आयोग की रिपोर्ट की तालिका में 15वें आयोग के लिए RLB की अनुशंसा ₹2,36,805 करोड़ और जारी ₹1,75,182 करोड़ (74.0%) दी गई है, पर यह जुलाई 2025 तक के आँकड़े हैं और केवल 2021-26 के आधार पर हैं। PIB का 94.98% बाद की तारीख़ का है और 2020-26 के पूरे आवंटन पर। हम इन दोनों को आपस में नहीं मिलाते।

महत्व: स्थानीय निकायों की वित्तीय स्वायत्तता

बड़ी राशि, पर शर्तों के साथ: 16वें आयोग के RLB अनुदान का आधा बेसिक भाग टाइड है, जो स्वच्छता, ठोस कचरा प्रबंधन और/या जल प्रबंधन के लिए है। कुल राशि का 20% परफ़ॉर्मेंस भाग है, जो अनटाइड है। इसलिए पूरी राशि पंचायतें अपनी मर्ज़ी से खर्च नहीं कर सकतीं।

जारी होना और उपयोग: PIB का 94.98% जारी होने का आँकड़ा है, खर्च या परिणाम का नहीं। 16वें आयोग की रिपोर्ट के ऊपर बताए अंश में पहले के चक्रों में जारी होने का प्रतिशत भी अलग-अलग है (हमने केवल तालिका की पंक्तियाँ देखीं)।

अपनी आय: विज्ञप्ति SAMARTH पोर्टल का उल्लेख करती है, पर पंचायतों की अपनी आय के आँकड़े नहीं देती। 16वें आयोग की रिपोर्ट में स्थानीय निकायों को अपने संसाधन जुटाने पर बल देने की बात है (हमने इस अंश का विस्तार नहीं पढ़ा)।

चुनौतियाँ और जो हमने नहीं पढ़ा

मंत्रालय का अपना सार: विज्ञप्ति उपलब्धियों का सरकारी सार है। इसमें राज्यवार अंतर या स्वतंत्र आँकड़े नहीं हैं। 84% का आधार भी उसमें नहीं लिखा, इसे हमने अन्य सरकारी स्रोतों से मिलाया है।

अलग आधार: जारी प्रतिशत, अनुशंसा की बढ़त और रिपोर्ट की तालिका का प्रतिशत तीन अलग आधार, तारीख़ और अवधि पर हैं। इन्हें एक संख्या में जोड़ना भ्रामक होगा।

जो हमने नहीं पढ़ा: हमने 15 जून 2026 की PIB विज्ञप्ति पूरी पढ़ी। 24 मार्च 2026 की PIB विज्ञप्ति, 16वें आयोग की रिपोर्ट का स्थानीय निकाय अध्याय (हमारी प्रति में कुछ अंक बिगड़े हैं, इसलिए केवल स्पष्ट अंश उपयोग हुए) और कार्रवाई-ज्ञापन के संबंधित पैराग्राफ़ ही पढ़े गए। रिपोर्ट के अन्य खंड, राज्यवार वितरण, अनुदान की शर्तें और वित्त मंत्रालय के ताज़ा आँकड़े नहीं पढ़े।

आगे की राह

इसे 15 जून 2026 तक की सरकारी जानकारी मानें। राशि की ताज़ा जारी स्थिति और शर्तों के लिए वित्त मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय के दिशानिर्देश देखे जाने चाहिए।

अवधारणा में अंतर

चार बातें अलग रखें: (1) जारी, आवंटित और अनुशंसित राशि; (2) PIB का कथन और हमारा मिलान; (3) अलग तारीख़ और आधार के प्रतिशत; (4) जारी होना और उपयोग।

मेंस दृष्टि

GS-II: पंचायती राज, स्थानीय शासन, केंद्र-राज्य वित्त; GS-III: समावेशी विकास और सार्वजनिक वित्त।

UPSC CSE Mains शैली: मौलिक अभ्यास प्रश्न

पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति सुधारने में वित्त आयोग के अनुदानों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। 15वें और 16वें वित्त आयोग के सरकारी आँकड़ों की तुलना करते समय किन सावधानियों की ज़रूरत है?

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) | 10 अंक

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: 73वें संशोधन और वित्त आयोग की भूमिका।

मुख्य भाग में: 15वें आयोग का आवंटन और जारी राशि; 16वें आयोग की अनुशंसा और घटक; 84% का आधार; जारी बनाम आवंटित बनाम अनुशंसित; शर्तें और अपनी आय।

निष्कर्ष में: अनुशंसा में बढ़त को पंचायतों को वास्तविक भुगतान न मानें; समान आधार पर आवंटन, जारी राशि और अनुशंसा की तुलना करते हुए अनुदान की शर्तों तथा पंचायतों की अपनी आय की भूमिका साथ परखें।

स्रोत

- PIB, पंचायती राज मंत्रालय: 12 वर्षों के पंचायत सुधार और नवाचार (15 जून 2026)
- PIB, पंचायती राज संस्थाएँ: लोकसभा में लिखित उत्तर (24 मार्च 2026)
- 16वाँ वित्त आयोग: रिपोर्ट, अध्याय 10 (स्थानीय निकायों को अनुदान), पंचायती राज मंत्रालय के पोर्टल पर उपलब्ध
- वित्त मंत्रालय: 16वें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों पर कार्रवाई-ज्ञापन (केंद्रीय बजट 2026)

स्रोत: 15 जून 2026 की PIB विज्ञप्ति पूरी पढ़ी गई। अन्य तीन स्रोतों के केवल संबंधित अंश पढ़े गए। रिपोर्ट के अध्याय में कुछ अंक बिगड़े हैं, इसलिए केवल स्पष्ट अंश लिए गए। राज्यवार वितरण, शर्तें और ताज़ा जारी स्थिति नहीं पढ़ी गई।

याद रखें: PIB के अनुसार 15वें आयोग के RLB आवंटन का 94.98% (₹2.82 लाख करोड़) जारी हुआ और 16वें आयोग ने ₹4,35,236 करोड़ की अनुशंसा की। “लगभग 84%” की बढ़त हमारे मिलान में 15वें आयोग के 2021-26 के ₹2,36,805 करोड़ की तुलना में बनती है (लगभग 83.8%); पूरे 2020-26 आवंटन ₹2,97,555 करोड़ से तुलना में बढ़त लगभग 46.3% है। आधार विज्ञप्ति में नहीं लिखा है, और अलग तारीख़ के जारी-प्रतिशत आपस में तुलनीय नहीं हैं।